

भारत में अब न्यूजीलैंड की वाइन और कीवीफ्रूट जैसे सामान हो जाएंगे सस्ते

भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, 5000 भारतीयों को वर्किंग वीजा मिलेगा, अब न्यूजीलैंड अगले 15 साल में भारत में 1.8 लाख करोड़ रुपए का करेगा निवेश

● नई दिल्ली / राज न्यूज नेटवर्क

भारत-न्यूजीलैंड के बीच सोमवार 27 अप्रैल को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) साइन हो गया है। अब भारत से न्यूजीलैंड भेजे जाने वाले लेदर प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, प्लास्टिक और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सामानों पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। जिससे इन श्रम-प्रधान क्षेत्रों यानी लेबर इंटेन्सिव सेक्टरों को सीधा लाभ होगा।

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इसे एक पीढ़ी में एक बार होने वाला समझौता बताया। वहीं मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने इसे भारत-न्यूजीलैंड आर्थिक संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत बताया है। पीयूष गोयल ने कहा कि यह एफटीए विश्वास, साझा मूल्यों और टिकाऊ आर्थिक विकास के साझा विजन को दर्शाता है। यह समझौता भारत के लिए एक्सपोर्टर्स के लिए बड़े अवसर खुलेंगे।

सर्विस सेक्टर में भारत ने आईटी, शिक्षा, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन और टूरिज्म जैसे हाई-वैल्यू सेक्टरों में बाजार पहुंच हासिल की है। समझौते के

करना है। एग्रीमेंट के तहत न्यूजीलैंड से अगले 15 साल में भारत में 20 बिलियन डॉलर (करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए) का निवेश आने की उम्मीद है। पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय व्यापारियों, विशेषकर आगरा के लेदर एक्सपोर्टर्स के लिए बड़े अवसर खुलेंगे।

सर्विस सेक्टर में भारत ने आईटी, शिक्षा, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन और टूरिज्म जैसे हाई-वैल्यू सेक्टरों में बाजार पहुंच हासिल की है। समझौते के

न्यूजीलैंड को कृषि उत्पादों पर रियायत

न्यूजीलैंड को भारतीय बाजार में पहुंच देने के लिए भारत ने अपनी 70 प्रतिशत टैरिफ लाइन खोल दी हैं। इसमें सेब, कीवीफ्रूट और मनुका हनी जैसे कृषि उत्पादों पर टैरिफ रियायत दी गई है, लेकिन ये कोटा लिमिट और मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस की शर्तों के साथ होंगी। इसके अलावा न्यूजीलैंड को भारत में अपने 54 प्रतिशत से ज्यादा एक्सपोर्ट पर तुरंत शुन्य ड्यूटी मिलेगी। इसमें शीप मीट, ऊन, कोयला और फॉरस्ट्री प्रोडक्ट्स शामिल हैं। सीफूड, आयरन, स्टील और एल्युमीनियम स्क्रूप पर टैरिफ को अगले 10 सालों में धीरे-धीरे खत्म किया जाएगा। हालांकि, भारत ने अपने घरेलू हितों की रक्षा के लिए डेयरी उत्पादों (दूध, क्रीम, पनीर आदि), घाज, दालें, चीनी, आर्म्स-अम्युनिशन और कुछ मेटल्स जैसे सेवेदनशील क्षेत्रों को रियायतों की लिस्ट से बाहर रखा है।

पीएम बोले- किसानों, युवाओं और एमएसएमई को होगा बड़ा फायदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को दोनों देशों की साझेदारी में एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता किसानों, युवाओं, महिलाओं, एमएसएमई, स्टार्टअप और छात्रों सहित अन्य वर्गों को काफ़ी फायदा पहुंचाएगा। मोदी ने यह भी कहा कि न्यूजीलैंड की 20 अरब डॉलर निवेश की प्रतिबद्धता कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और प्रौद्योगिकी में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करेगी। इससे दोनों देशों के लिए ज्यादा समृद्ध और गतिशील भविष्य का रास्ता खुलेगा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया संघ एक्स पर लिखा, आज भारत-न्यूजीलैंड साझेदारी में एक ऐतिहासिक क्षण है। मुझे खुशी है कि आज हस्ताक्षर किये गये भारत-न्यूजीलैंड एफटीए हमारी विकासत्मक साझेदारी को अभूतपूर्व गति देगा। यह उस मजबूत भरोसे, साझा मूल्यों और महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, जो हमारे दोनों देशों को जोड़ते हैं। उन्होंने कहा, यह समझौता हमारे किसानों, युवाओं, महिलाओं, एमएसएमई, कारीगरों, स्टार्टअप, छात्रों और इनोवेशन करने वालों को बहुत फायदा पहुंचाएगा। यह विकास के नए रास्ते खोलेंगा, अवसर पैदा करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में हमारे तालमेल को मजबूत करेगा।

चावल, गेहूं के भाव बढ़े और खाद्य तेलों में नरमी

● नई दिल्ली / राज न्यूज नेटवर्क

घरेलू थोक जिस बाजारों में सोमवार को चावल का औसत भाव बढ़ गया। चावल के साथ गेहूं में भी तेजी देखी गयी। चीनी और खाद्य तेलों के भाव टूट गये जबकि दालों के दामों में घट-बढ़ रही। औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत दो रुपये बढ़कर 3,849 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गयी। गेहूं चार रुपये महंगा हुआ और 2,784 रुपये प्रति क्विंटल बोला गया।

आटे की कीमत 10 रुपये घट गयी। दाल-दलहनो में उतार-चढ़ाव रहा। तुअर दाल और मसूर दाल की औसत कीमत 23-23 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी। उड़द दाल 14 रुपये महंगी हुई। मूंग दाल में 33 रुपये और चना दाल में 11 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट देखी गयी। मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में जुलाई का पाप ऑयल वायदा 62 रििंगिट टूटकर 4,535 रििंगिट प्रति टन रह गया। जुलाई का अमेरिकी सोया तेल वायदा भी 0.42 प्रतिशत नीचे 71.03 सेंट प्रति पौंड के भाव बोला गया। स्थानीय बाजारों में सोया तेल की औसत कीमत 92 रुपये और सूरजमुखी तेल की 67 रुपये प्रति क्विंटल गिर गयी।

सन फार्मा करेगी अमेरिकी दवा कंपनी का अधिग्रहण

● मुंबई / राज न्यूज नेटवर्क

भारतीय दवा कंपनी सन फार्मा इसी क्षेत्र की अमेरिकी कंपनी ऑर्गानॉन का 3.99 अरब डॉलर में अधिग्रहण करेगी। दोनों कंपनियों की संयुक्त प्रेस विज्ञापित में बताया गया है कि इस संबंध में पक्का समझौता हो गया है।

यह अधिग्रहण सन फार्मा की एक पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी सहयोगी कंपनी के माध्यम से किया जायेगी। इस सौदे के तहत ऑर्गानॉन के शेयरधारकों को प्रति इक्विटी शेयर 14 डॉलर का भुगतान किया जायेगा। इस घोषणा के बाद सन फार्मा का शेयर आज सात प्रतिशत चढ़कर 1,733 रुपये पर पहुंच गया। ऑर्गानॉन का वर्तमान उद्यम मूल्यांकन 11.75 अरब डॉलर है। पिछले साल उसका राजस्व 6.2 अरब डॉलर और परिचालन लाभ 1.9 अरब डॉलर रहा था। कंपनी पर 31 दिसंबर 2025 को 8.6 अरब डॉलर का कर्ज था और उसके पास 57.4 करोड़ डॉलर की नकदी थी।

एनपीएस में सीधे बैंक खाते में आएगा मेडिकल भत्ता बिना बिल जमा किए हर तिमाही सीधे आपके बैंक खाते में पैसा आ जाएगा

● नई दिल्ली / राज न्यूज नेटवर्क

केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) से जुड़े पेंशनभोगियों और उनके परिवारों के लिए प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब बुजुर्ग पेंशनर्स को फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (एफएमए) यानी चिकित्सा भत्ता पाने का सिस्टम आसान और ऑटोमैटिक कर दिया गया है।

वित्त मंत्रालय ने 16 अप्रैल को जारी अपने नए आदेश में प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब बुजुर्ग पेंशनर्स को फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (एफएमए) के लिए न तो बार-बार मेडिकल बिल जमा करने पड़ेंगे और न ही दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे। पूरी व्यवस्था बैंक के जरिए होगी और यह भत्ता सीधे उनके बैंक खाते में आ जाएगा। मंत्रालय ने आदेश में बताया है कि अब इस भत्ते का भुगतान बैंकों के सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीपीसी) के जरिए होगा। यह सिस्टम पूरी तरह

ऑटोमैटिक रहेगा, इसलिए पेंशनर्स को कोई बिल या दावा देने की जरूरत नहीं होगी। प्रक्रिया ऐसी होगी कि सेंट्रल पेंशन एकाउंटिंग ऑफिस (सीपीएओ) पहले एंलिजिबिलिटी की जांच करेगा और मंजूरी मिलने पर बैंक को स्पेशल सील अथॉरिटी (एसएसए) जारी करेगा। इसके आधार पर बैंक का सीपीपीसी डिपार्टमेंट तय दर के अनुसार हर तीन महीने में मेडिकल भत्ते की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर देगा।

सरकार ने भले ही बिल जमा करने की प्रक्रिया खत्म कर दी है, लेकिन एक जरूरी नियम अब भी लागू रहेगा।

एंलिजिबिलिटी की जांच करेगा और मंजूरी मिलने पर बैंक को स्पेशल सील अथॉरिटी (एसएसए) जारी करेगा। इसके आधार पर बैंक का सीपीपीसी डिपार्टमेंट तय दर के अनुसार हर तीन महीने में मेडिकल भत्ते की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर देगा।

सरकार ने भले ही बिल जमा करने की प्रक्रिया खत्म कर दी है, लेकिन एक जरूरी नियम अब भी लागू रहेगा।



मृत्यु के बाद परिवार के लिए क्या है नियम

सरकार ने परिवारों के लिए प्रक्रिया भी आसान रखी है। अगर किसी पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है और पात्र परिवार के सदस्य का नाम पहले से दर्ज है, तो वे मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ सीधे बैंक में अपेदन कर सकते हैं और उन्हें मेडिकल भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं, अगर नाम रिकॉर्ड में नहीं है, तो संबंधित डिपार्टमेंट के जरिए नई मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा, पेंशनभोगियों के पास यह विकल्प भी है कि वे फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (एफएमए) की जगह सीजीएसएस की ओपीडी सुविधा चुन सकते हैं। इस व्यवस्था में बैंक पहले भत्ते का भुगतान करेंगे और बाद में सरकार उन्हें इसकी प्रतिलिपि करेगी। इसका मकसद प्रक्रिया को आसान बनाना और पेंशनभोगियों को कागजी झंझट से राहत देना है।

ओरेकल 30 साल से काम कर रहे कर्मचारियों को निकाला

● नई दिल्ली / राज न्यूज नेटवर्क

टेक जगत की नामी कंपनी ओरेकल में इन दिनों छंटनी का दौर चल रहा है, लेकिन इस बार का तरीका काफी हैरान करने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने उन अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जिन्होंने अपनी जिदगी के 30 से 33 साल इस संस्थान को दिए थे। एक झटके में दशकों पुरानी वफादारी को दरकिनार कर इन अनुभवी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जब 1 अप्रैल को सुबह 6 बजे ईमेल के जरिए दुनियाभर के 30 हजार कर्मचारियों की छंटनी की गई तो, उनमें से एक मेल नीना लुईस के पास भी पहुंचा, जो एक सुरक्षा प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने ओरेकल 33 से ज्यादा का समय बिताया है। लुईस ने लिंकडइन पर पोस्ट किया कि ओरेकल में 30 साल से अधिक साल के बाद, आज मुझे भी लगभग 30,000 लोगों की तरह नौकरी से निकाल दिया गया है। मेरे कई बेहतरीन सहकर्मी को भी नौकरी से निकाल दिया गया है। उन्होंने इस बात पर अटकलें लगाया शुरू कर दिया कि हायरिंग कैसे हो रही होगी।

अहमदाबाद मंडल के 4 कर्मचारी संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित



● अहमदाबाद / राज न्यूज नेटवर्क

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक रामाश्रय पाण्डेय ने अहमदाबाद मंडल के चार कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य, सतर्कता एवं सुरक्षित ट्रेन संचालन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मैन ऑफ द मन्थ (फरवरी-2026) संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रभाष कुमार यादव ने अपनी ड्यूटी के दौरान दो अलग-अलग अवसरों पर उत्तर स्तर की सतर्कता का परिचय दिया। सुबोध कुमार ने ड्यूटी के दौरान गुजरती ट्रेन के एक वैगन में हैंगिंग पार्ट (सेफ्टी रॉड) देखा। उन्होंने

तुरंत लाल संकेत देकर ट्रेन को रुकवाने की प्रक्रिया शुरू की और स्टेशन मास्टर को सूचित किया।

दीपक कुमार एस. ने रोलिंग एग्जामिनेशन के दौरान वैगनों में पंथीर तकनीकी दोष जैसे ग्रीस सील का खिसकना एवं सीटीआरबी कप का टूटना समय रहते पहचाना। वहीं, दीपक कुमार ने ड्यूटी के दौरान यह पाया कि एक ट्रेन निर्धारित 20 किमी/घंटा की गति सीमा से अधिक गति से चल रही थी। उन्होंने तत्परा दिखाते हुए लाल झंडा दिखाकर ट्रेन को रोका। उनकी सजगता और कर्तव्यनिष्ठा के कारण संभावित खतरे को दलना संभव हुआ। इन सभी कर्मचारियों की सतर्कता, तत्परता एवं कर्तव्यनिष्ठा भारतीय रेलवे की संरक्षा संस्कृति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पश्चिम रेलवे को इन पर गर्व है।

उपलब्धि पतंजलि के प्रयोग से उत्तर भारत में चंदन की खेती को मिली दिशा

पतंजलि ने दिखाई चंदन वन की राह

● हरिद्वार / राज न्यूज नेटवर्क

देश में चंदन की खेती लंबे समय तक दक्षिण भारत तक सीमित मानी जाती रही, लेकिन अब यह धारणा बदल रही है। उत्तराखंड में पतंजलि की ओर से विकसित चंदन वनछ मॉडल ने साबित किया है कि अनुकूल परिस्थितियों में उत्तर भारत में भी चंदन की सफल खेती संभव है। प्रदेश के कई जिलों में इसके सकारात्मक उदाहरण सामने आ चुके हैं।

हरिद्वार स्थित पतंजलि के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने करीब दो दशक पहले चंदन की

खेती पर प्रयोग शुरू किए थे। उस समय उत्तर भारत में इसकी खेती लगभग न के बराबर थी। पतंजलि के रिसर्च सेंटर और औषधीय उद्यान में लगाए गए चंदन के पौधों पर किए गए अध्ययन में सकारात्मक परिणाम मिले, जिसके बाद राज्य के कई जिलों में किसानों

और निजी संस्थाओं ने इस मॉडल को अपनाया शुरू कर दिया। विशेषज्ञों के अनुसार चंदन एक अर्ध-परजीवी वृक्ष है, जिसकी वृद्धि के लिए अन्य पौधों की जड़ों से पोषण आवश्यक होता है। इसलिए इसकी खेती वैज्ञानिक पद्धति और उचित प्रबंधन पर निर्भर करती है।

